साप्ताहिक
जागत गांव हमार
पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक
RNI-MPHIN/2015/72544
चौपाल से भोपाल तक
भोपाल, सोमवार, 03-09 मार्च 2025 वर्ष-10, अंक-46
भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित
पृष्ठः-8,मूल्यः- 2 रुपए

सागर जिले के गढ़ाकोटा में रहस मेले और किसान सम्मेलन में सीएम डॉ. मोहन यादव ने किया वादा

अगले साल मप्र सरकार 2700 रुपए क्विंटल एमएसपी पर खरीदेगी गेहूं

» 2600 रुपए क्विंटल एमएसपी पर गेहूं खरीदेगी राज्य सरकार

» चावल पर 2000 रुपए प्रति हैक्टेयर बोनस दिया जाएगा

भोपाल। जागत गांव हमार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सागर के गढ़ाकोटा में तीन दिवसीय सांस्कृतिक रहस मेले में आयोजित किसान महा सम्मेलन में कहा कि बुंदेलखंड वीरों की धरती है। वीरों के बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने किसानों के लिए बड़ी सौगात देते हुए कहा कि सरकार अब किसानों से 2600 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदेगी। उन्होंने कहा कि सागर-दमोह रोड को फोरलेन बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने मंच से 5 हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के हितलाभ भी वितरित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा सीमा पर जवान और खेत पर किसान को सम्मान देने का कार्य किया जा रहा है। किसान की आय दोगुनी करने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार लगातार कार्य कर रही है। अगले कुछ वर्षों में बुंदेलखंड की लाखों हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। किसान अपनी जमीन बचाकर रखें, उन्हें उनकी जमीन का पूरा लाभ मिलेगा और उनकी कृषि समृद्ध होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तक मैंने 9 रस ही देखे थे आज मैंने 10वां रस भी देख लिया। इस रहस मेला के आनंद में जो 10वां रस मिला है वह अद्भुत है। मध्यप्रदेश सरकार इस वर्ष किसानों का गेहूं 2600 रुपए प्रति क्विंटल खरीदेगी और अगले वर्ष यह बढ़ाकर 2700 रुपए प्रति क्विंटल खरीदने का मैं वादा करता हूं। इसी प्रकार चावल पर 2000 रुपए प्रति हैक्टेयर बोनस दिया जाएगा। इसी प्रकार दूध का उत्पादन करने वालों को बोनस दिया जाएगा।

नदी जोड़ो अभियान

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी के नदी जोड़ो अभियान के सपने को प्रधानमंत्री मोदी पूरा कर रहे हैं। इसमें केन-बेतवा लिंक परियोजना के माध्यम से बुंदेलखंड को लाभान्वित करने का कार्य किया जा रहा है। इसी प्रकार महाराष्ट्र सरकार से मिलकर भी नदी जोड़ो अभियान प्रारंभ किया जाएगा।

कोई योजना नहीं होगी बंद

मध्यप्रदेश सरकार ने फूड इंडस्ट्रीज लगाने वालों को सरकार 40 प्रतिशत सब्सिडी देगी। भारत दुनिया में सबसे अधिक युवाओं की आबादी वाला देश है। मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा संचालित लाड़ली बहना योजना, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जैसी सभी योजनाएं जारी रहेंगी। उन्होंने सागर के संपूर्ण विकास के लिए संकल्प लेते हुए कहा कि इसके लिए लगातार कार्य किया जा रहा है।

किसानों की आय होगी दोगुना

कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंषाना ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री किसानों के हित के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। किसान खुशहाल होगा तो देश और प्रदेश खुशहाल होगा। किसानों को योजनाओं का लाभ देने के लिए किसान मेला एवं कार्य-शालाओं का लगातार आयोजन किया जा रहा है।

अब तक तीन लाख किसानों ने कराया पंजीयन

सरकार एमएसपी पर 80 लाख टन खरीदेगी गेहूं

इधर, मध्य प्रदेश में इस बार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 80 लाख टन गेहूं खरीदा जाएगा। केंद्र सरकार ने प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य 2,425 रुपये निर्धारित किया है लेकिन मोहन सरकार 2,600 रुपए के हिसाब से भुगतान करेगी। उपार्जन की शुरुआत 15 मार्च को इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग से होगी। बाकी संभागों में 17 मार्च से पांच मई 2025 तक गेहूं उपार्जन केंद्रों पर लिया जाएगा। समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए अभी तक लगभग तीन लाख किसान पंजीयन करा चुके हैं। भुगतान के लिए उत्तर प्रदेश का माडल लागू करने की तैयारी है, जिसमें उपज विक्रय के 48 घंटे के भीतर भुगतान किया जाता है। मध्य प्रदेश देश के उन प्रमुख राज्यों में शामिल है, जहां न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से उपज खरीदी जाती है। केंद्र सरकार के लिए विकेंद्रीकृत प्रणाली के अंतर्गत राज्य नागरिक आपूर्ति निगम और राज्य सहकारी विपणन संघ उपार्जन का का काम करते हैं। चार हजार केंद्रों पर उपार्जन होगा। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने इसकी तैयारी प्रारंभ कर दी है। पोर्टल पर किसानों का पंजीयन किया जा रहा है। इस बार 80 लाख टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा है।

- लघु-सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी
- प्रति क्विंटल 2,600 रु. के हिसाब से होगा भुगतान
- 15 मार्च से प्रदेश में होगी समर्थन मूल्य की खरीदी
- इंदौर, उज्जैन, भोपाल, नर्मदापुरम से होगी शुरुआत
- केंद्र सरकार ने इस साल समर्थन मूल्य 2,425 तय किया

आरबीआई का चौंकाने वाला खुलासा-बिचौलियों की जेब में जा रहा 50 फीसदी धन

सावधान! अन्नदाताओं को फसलों का मिल रहा आधा ही पैसा

भोपाल। जागत गांव हमार

देश के उपभोक्ता जो भी रबी फसलों की उपज खरीदते हैं, उसका 40 से 67 परसेंट पैसा किसानों के पास जाता है। यह जानकारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक सर्वे में सामने आई है। इसमें पैसे के भुगतान के बारे में भी बताया गया है। स्टडी कहती है कि उपज से जुड़े लेनदेन यानी ट्रांजैक्शन में नकद का बोलबाला है, मगर ऑनलाइन पेमेंट ने भी बड़ा उछाल दर्ज किया गया है। इस सर्वे में रबी फसलों को शामिल किया गया है जो मई-जुलाई 2024 में उगाई और बेची गईं। सर्वे बताता है कि किसानों को उन उपजों का दाम अधिक मिला जो जल्द खराब होने वाली नहीं है, जबकि फल और सब्जियों का शेयर बहुत कम रहा। देश के गेहूं किसानों को सबसे अधिक लाभ मिला है क्योंकि उपभोक्ता मूल्य का 67 परसेंट हिस्सा उनके पास गया है। इसकी

बड़ी वजह है कि गेहूं एक नोटिफाइड कमॉडिटी है जिसका बड़ा हिस्सा सरकारी एजेंसियां एक सिस्टम के जरिये खरीदती हैं। चावल किसानों की बात करें तो उन्हें खुदरा दाम का 52 परसेंट हिस्सा मिला। चावल का यह ट्रेंड पिछले सर्वे में भी देखा गया था। इससे पता चलता है कि चावल की बिक्री में किसानों का एकसमान ट्रेंड चला आ रहा है। 2024 के सर्वे में पता चला कि गेहूं किसानों में से लगभग एक-चौथाई ने खरीद सिस्टम के तहत सरकार को अपनी उपज बेची है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपजों की खरीद किसानों को बाजार का विकल्प देती है। आरबीआई की सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि 67 प्रतिशत लोगों का अनुमान बताता है कि उपभोक्ता मूल्य में गेहूं किसानों की हिस्सेदारी 53 से 74 प्रतिशत के बीच है। रिपोर्ट बताती है कि किसानों को नहीं खराब होने वाली उपजों का अधिक दाम मिला है जबकि फल और सब्जियां, जो जल्द खराब होती हैं, उसके सबसे कम पैसे मिले हैं। व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं की बात करें तो खराब होने वाली उपजों में इन दोनों का शेयर 50 परसेंट से अधिक है। यानी फलों और सब्जियों का अधिक पैसा व्यापारियों और खुदरा दुकानदारों के पास जाता है।

सरसों किसानों की हिस्सेदारी 52 फीसदी

सर्वे में कहा गया है कि दालों में मसूर किसानों को कुल दाम का 66 प्रतिशत और चना किसानों को 60 प्रतिशत मिलता है। दालों की खेती बढ़ाने के लिए सरकार किसानों को कई सुविधाएं दे रही है, क्योंकि यह मुख्य रूप से छोटे किसानों द्वारा उगाया जाता है और इससे आयात पर निर्भरता को कम करना है। तिलहनों में रेपसीड और सरसों के लिए किसानों की हिस्सेदारी 52 प्रतिशत रही, जबकि 2021 के एक अध्ययन में 55 प्रतिशत का अनुमान लगाया गया था।

अधिकांश शहरी बस्तियां

सर्वे में किसानों, व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं को शामिल करके 12 रबी फसलों के लिए 18 राज्यों में 86 केंद्रों में मंडियों या गांवों को लिया गया। इसमें अलग-अलग जगहों के 10,699 लोग शामिल थे। यह सर्वे मई-जुलाई 2024 के दौरान आयोजित किया गया था, जिसमें अधिकांश शहरी बस्तियां शामिल रहीं।

सीएम का दावा-मध्यप्रदेश अगले पांच वर्ष में राज्य की अर्थव्यवस्था को करेगा दोगुना

मोदी-मोहन शुभ निवेश का महाकुंभ

» विश्व जो विश्वास भारत पर कर रहा है, देश को वही विश्वास मप्र पर

» पीएम ने उद्योग-रोजगार वर्ष के निर्णय के लिए सीएम मोहन को सराहा

भोपाल। प्रधान संपादक

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि दो दिनी समिट में 25 हजार से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए। इसमें 60 देशों के 100 से ज्यादा विदेशी प्रतिनिधियों ने मध्य प्रदेश में निवेश और व्यापारिक सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की। जीआईएस में 9 देशों ने पार्टनर कंट्री के रूप में सहभागिता की। इसमें कनाडा, जर्मनी, इटली, जर्मनी, मोरक्को, पोलेंड, रूस, रवांडा, यूनाइटेड किंगडम शामिल है। वहीं, समिट के दौरान सीएम से 70 से अधिक प्रमुख उद्योग के उद्योगपतियों, संगठनों के साथ वन टू वन मीटिंग की गई। सीएम ने बताया कि जीआईएस में 600 से अधिक बीटूजी बैठकें और पांच हजार से अधिक बीटूबी बैठकें आयोजित हुई। छह विभागीय समिट आईटी एवं टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, एमएसएमई और स्टार्टअप, टूरिज्म, माइनिंग और अर्बन डेवलपमेंट समिट शामिल है। इन मिनी समिट में करीब 100 सेक्टर एक्सपर्ट, उद्योगपतियों ने स्पीकर्स, पेनलिस्ट के रूप में भाग लिया। साथ ही समिट में 10 थीमैटिक/ सेक्टोरल सेशंस का आयोजन किया गया।

जीआईएस में दो दिन की बैठक में सरकार को विभागवार निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इसमें औद्योगिक नीति एवं निवेश संवर्धन विभाग निवेश और रोजगार दोनों ही मामलों में अव्वल है। वहीं, रोजगार में दूसरे नंबर पर शहरी विकास विभाग है। सरकार की तरफ से विभागवार निवेश और रोजगार को लेकर जारी आंकड़े के अनुसार औद्योगिक नीति एवं निवेश संवर्धन विभाग में 8.616 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले। इनसे 6 लाख रोजगार के अवसर बनने की संभावना है। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग में 5.72 लाख करोड़ का निवेश और 1.4 लाख रोजगार सृजित होने का अनुमान है। इसके अलावा खनन एवं खनिज संसाधन विभाग में 3.22 लाख करोड़ का निवेश और 55 हजार रोजगार, शहरी विकास एवं आवास विभाग 1.97 लाख करोड़ का निवेश और 2.3 लाख रोजगार के अवसर, ऊर्जा विभाग में 1.47 लाख करोड का निवेश और 20 हजार पद, पर्यटन विभाग 68 लाख हजार करोड़ और 1.2 लाख रोजगार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग 64 हजार करोड़ का निवेश और 1.8 लाख रोजगार के अवसर, तकनीक शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग में 43 हजार करोड़ का निवेश और 51 हजार रोजगार, एमएसएमई 21 हजार करोड़ रुपए और 1.3 लाख रोजगार, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग 17 हजार करोड़ रुपए और 49 हजार रोजगार, उच्च शिक्षा विभाग 7 हजार करोड़ रुपए और 15 हजार रोजगार, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में 4 हजार करोड़ रुपए का निवेश और 8 हजार रोजगार, चिकित्सा शिक्षा विभाग 3 हजार करोड़ और 9 हजार रोजगार, विमानन विभाग 1400 करोड़ को निवेश और 1 हजार रोजगार, पीडब्ल्यूडी 1.30 लाख करोड़ और चार हजार रोजगार के अवसर मिलने का अनुमान है। इसके अलावा अदाणी ग्रुप अलग-अलग सेक्टर में 2.10 लाख करोड़ का निवेश प्रदेश में कर रहा है। इससे 1 लाख रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

» जो एक बार मध्यप्रदेश आता है, वह यहीं का होकर रह जाता है...

» अनंत संभावनाओं के ध्येय वाक्य के साथ आरंभ हुई ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट

» विमानन सेवा के लिए ग्वालियर-जबलपुर के एयरपोर्ट को विस्तार दिया गया

» विश्व में यह मान्यता है कि भारत जो कहता है-वह करके दिखाता है

» महाकाल महालोक के दर्शन प्रदान करते हैं अलौकिक अनुभूति

» निवेश और रोजगार में औद्योगिक नीति विभाग अव्वल

» रोजगार में दूसरे नंबर पर शहरी विकास विभाग पहुंचा

» जीआईएस में 60 देशों के 100 विदेशी प्रतिनिधि आए

मोदी ने मप्र की 18 उद्योग फ्रैंडली नीतियां लॉन्च

प्रधानमंत्री ने निवेशकों को दिया 'ट्रिपल-टी' का मंत्र

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के लिए लागू 18 नवीन नीतियों का शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत मप्र उद्योग नीति 2025, एमएसएमई नीति, एक्सपोर्ट प्रमोशन नीति, लॉजिस्टिक्स नीति, स्टार्टअप नीति, मध्यप्रदेश एनीमेशन, वीआर, गैमिंग कामिक्स और विस्तारित रियलिटि नीति, जीसीसी नीति, सेमी कंडक्टर नीति, ड्रोन संवर्धन और उपयोग नीति, फिल्म पर्यटन नीति, पर्यटन नीति, पम्पड हाइड्रो स्टोरेज नीति, सिटी गैस डिस्ट्रिब्यूशन नीति, विमानन नीति, नवकरणीय ऊर्जा नीति, स्वास्थ निवेश प्रोत्साहन नीति और एकीकृत टाउनशिप नीति शामिल हैं। पीएम मोदी ने समिट में आए उद्योगपतियों को मप्र में निवेश के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा कि यहां 300 से अधिक इंडस्ट्री जोन हैं। निवेश की अपार संभावनाएं हैं। प्रदेश में 31 हजार मेगावॉट सरपल्स एनर्जी है। जिसमें 30 फीसदी रिन्यूएबल एनर्जी है। कुछ दिन पहले ही ओंकारेश्वर में फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का शुभारंभ हुआ है। एनर्जी सेक्टर में आए बूम का मप्र को लाभ मिला है। हाल ही में 45 हजार करोड़ लागत की केन-बेतवा लिंक परियोजना की आधारशिला रखी गई, जिससे 10 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई क्षमता बढ़ेगी, परिणामस्वरूप प्रदेश में कपड़ा उद्योग और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर बढ़ेगा।

ईवी में तेजी से बढ़ रहा मध्यप्रदेश

दो दशक पहले लोग मध्यप्रदेश में निवेश करने से डरते थे। जिस प्रदेश में बसें ठीक से नहीं चल पाती थीं, वह राज्य अब इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। जनवरी 2025 तक प्रदेश में दो लाख इलेक्ट्रिक वाहन रजिस्टर्ड हुए हैं, जो दर्शाता है कि नए क्षेत्रों में भी मप्र निवेश आकर्षित कर रहा है। लीथियम बैटरी और न्यूक्लीयर एनर्जी में भी निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मप्र में शत-प्रतिशत रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण किया जा चुका है। रानी कमलापति स्टेशन के चित्र सभी का मन मोह रहे हैं। इसी तर्ज पर प्रदेश के 80 रेलवे स्टेशनों को विकसित किया जा रहा है। विमानन सेवा के लिए ग्वालियर और जबलपुर के एयरपोर्ट को विस्तार दिया गया है।

इन्वेस्ट मध्यप्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 24 25 फरवरी 2025, भोपाल

जीआईएस-2025 में प्राप्त विभागवार निवेश प्रस्ताव

विभाग	प्रस्तावित निवेश करोड़ में	प्रस्तावित रोजगार	विभाग	प्रस्तावित निवेश करोड़ में	प्रस्तावित रोजगार
नवीन ऊर्जा विभाग	5.72 लाख करोड़	1.4 लाख	स्वास्थ्य विभाग	17 हजार करोड़	49 हजार
औद्योगिक विभाग	8.616 लाख करोड़	6 लाख	उच्च शिक्षा विभाग	7 हजार करोड़	15 हजार
खनिज विभाग	3. 22 लाख करोड़	55 हजार	उद्यानिकी विभाग	4 हजार करोड़	8 हजार
शहरी विकास विभाग	1.97 लाख करोड़	2.3 लाख	चिकित्सा शिक्षा विभाग	3 हजार करोड़	9 हजार
ऊर्जा विभाग	1. 47 लाख करोड़	20 हजार	विमानन विभाग	1400 करोड़	1 हजार
पर्यटन विभाग	68 हजार करोड़	1.2 लाख	पीडब्ल्यूडी विभाग	1.30 लाख करोड़	4 हजार
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	64 हजार करोड़	1.8 लाख	कुल	24.51 लाख करोड़	16.34 लाख
तकनीकी शिक्षा विभाग	43 हजार करोड़	51 हजार	अडानी ग्रुप	2.10 लाख करोड़	1 लाख
एमएसएमई	21 हजार करोड़	1.3 लाख	कुल योग	26.61 लाख करोड़	17.34 लाख

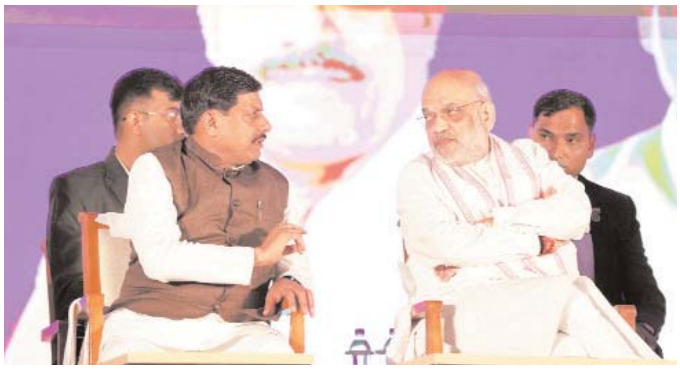

मध्य प्रदेश को कुल प्राप्त निवेश प्रस्तावों की जानकारी

कार्यक्रम	प्रस्तावित निवेश करोड़ में	प्रस्तावित रोजगार
रीजनल इण्डस्ट्री कॉनक्लेव	2.34 लाख करोड़	2.74 लाख
इन्टरेक्टिव सेशन	1.82 लाख करोड़	1.32 लाख
जीआईएस में प्राप्त निवेश प्रस्ताव	26.61 लाख करोड़	17.34 लाख
कुल प्राप्त निवेश प्रस्ताव	**30.77 लाख करोड़**	**21.40 लाख**

» ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के भव्य आयोजन के लिए मुख्यमंत्री दी बधाई

» बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा निवेशक भी मप्र के लिए है अतिथि

कॉटन कैपिटल एमपी

प्रधानमंत्री ने मध्यप्रदेश को देश का कॉटन कैपिटल बताते हुए कहा कि कपड़ा उद्योग और कॉटन सप्लाय में मध्यप्रदेश, देश का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहां का मलबरी सिल्क और चंदेरी साड़ियां भी बहुत पसंद की जाती हैं। देश में बन रहे सात बड़े टेक्सटाइल पार्क में से एक मप्र में है। देश के टूरिज्म सेक्टर में मध्यप्रदेश अजब भी है और गजब भी है। नर्मदा के किनारे पर्यटन का पर्याप्त विकास हुआ है। प्रदेश में मेडिकल टूरिज्म की भी अपार संभावनाएं हैं।

ट्रिपल-टी देश के विकास को देंगे गति

पीएम मोदी ने कहा कि टेक्सटाइल, टूरिज्म और टेक्नोलॉजी आगामी वर्षों में देश के विकास को गति देंगे। मध्यप्रदेश सहित देश में मेडिकल टूरिज्म की अपार संभावनाए हैं। हेल्थ एंड वेलनेस क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार एमएसएमई सेक्टर को गति देने के लिए एमएसएमई केन्द्रित सप्लाई चैन को विकसित करने की दिशा में कार्य कर रही है। इस सेक्टर में कार्यरत उद्यमियों को प्रोत्साहन प्रदान किए जा रहे हैं।

सबसे ज्यादा खनिज संपदा पैदा करने वाला राज्य हमारा मप्र
मप्र का कॉटन कैपिटल के साथ फूड प्रोसेसिंग का राज्य बना

शाह बोले-करिए निवेश..देश और मध्यप्रदेश में मजबूत सरकार

-प्रदेश सरकार की पारदर्शिता पूर्ण कार्यप्रणाली ने निवेशकों को आकर्षित किया

-भारत के दिल मध्यप्रदेश में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और इको सिस्टम बन चुका

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार और सभी राज्यों की टीम इकट्ठा होकर समग्र भारत का विकास करेगी। इस दिशा में जाने के लक्ष्य को मध्य प्रदेश की यह समिट पूरा करने में सहायक होगी। मध्य प्रदेश सरकार ने जो नीतियां बनाई हैं। वह आगे बढ़ेंगी और भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएगी। निवेशक सबसे पहले एक स्थाई सरकार खोजता है। देश और मध्यप्रदेश में मजबूत सरकार विद्यमान है। मप्र में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो चुका है। यहां स्टील वर्क फोर्स की एक बड़ी फौज है। बेहतरीन इको सिस्टम भी प्रशासन ने उपलब्ध कराया है। मार्केट का एक्सेस भी प्रदेश से ज्यादा और कोई राज्य को उपलब्ध नहीं है और डिमांड ओरिएंटेड इकोनामी भी अब यहां पर है। मध्य प्रदेश इन्वेस्टमेंट के लिए एक बड़ा आकर्षण केंद्र पूरे भारत में बना हुआ है।

मप्र देश का कॉटन कैपिटल

शाह ने कहा कि 20 साल पहले मध्य प्रदेश को गिनती बीमारू राज्यों में की जाती थी। न सड़क थी न बिजली। भाजपा की सरकार ने छह लाख किलोमीटर सड़कों का नेटवर्क बनाया। देश भर में सबसे ज्यादा खनिज संपदा प्राप्त करने वाले राज्यों में हमारा मध्यप्रदेश है। यह देश का कॉटन कैपिटल भी बन रहा है। देश के 25 प्रतिशत ऑर्गेनिक कॉटन का सप्लाई यहां से होती है।

भारत में टॉप अचीवर बनेगा मप्र

शाह ने कहा कि मध्य प्रदेश पूरे भारत में टॉप अचीवर बनेगा। बैंकिंग की बात की जाए तो दस साल में 56 करोड़ लोगों को बैंकिंग से केंद्र सरकार ने जोड़ा है। इन लोगों को आजादी के 75 साल तक बैंक अकाउंट खोलने का सौभाग्य भी नहीं मिला था। जो सेक्टर विश्व की अर्थ नीति तय करने वाले हैं विश्व की इकोनॉमी की दिशा तय करने वाले है। चाहे वो ग्रीन एनर्जी हो या इलेक्ट्रिक व्हीकल, मध्य प्रदेश उसमें भी आगे है।

मोहन बोले-विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने मप्र प्रतिबद्ध

हमारा लक्ष्य देश को 35 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व और मार्गदर्शन में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सतत विकास और औद्योगिक निवेश की दिशा में नए कदम बढ़ाऐ जा रहे है। जीआईएस की थीम अनंत संभावनाएं है, जो प्रदेश में उद्योग और निवेश की असीमित संभावनाओं को दर्शाती है। अनंत संभावनाएं केवल एक विचार नहीं, बल्कि मप्र के हर क्षेत्र में अवसरों की व्यापकता को दर्शाने वाला दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास का मंत्र दिया, जिसमें यह संदेश समाहित है कि जब संभावनाओं के अनंत आकाश में हम साथ मिलकर आशा की ज्योत जलाते हैं, तो एक नहीं, बल्कि सभी के आंगन रोशन होते हैं और यही हमारी सनातन संस्कृति है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प भारतवासियों ने लिया है। हमारा लक्ष्य देश को 35 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है। विकसित भारत के इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए विकसित मध्यप्रदेश समस्त प्रदेशवासियों के साथ महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में राज्य सरकार अगले 5 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है।

नवकरणीय

कंपनी	निवेश संभाग
अवाडा समूह	जबलपुर
एक्सिस एनर्जी	जबलपुर
एनएसएल	जबलपुर
टोरेंट पावर	इंदौर
जिंदल इंडिया	भोपाल
एमकेसी इंफ्रास्ट्रक्चर	जबलपुर
केपीआई ग्रीन एनर्जी	भोपाल
केपी समूह	भोपाल

ऊर्जा विभाग

कंपनी	निवेश संभाग
हेक्सा क्लाइमेट	उज्जैन
ओरियाना पावर	रीवा
मैक्लेक	जबलपुर
डीसीओ रिन्यूएबल	रीवा
एएमपीआईएन ऊर्जा	इंदौर
भास्कर सोलरटैक	इंदौर

शहरी विकास

कंपनी	निवेश संभाग
समदरिया बिल्डर	जबलपुर
टीम रीथिंकिंग रौनक ग्रुप	इंदौर
ट्रेजर ग्रुप	भोपाल
वैश्विक दुनिया	इंदौर
एचवाईडी टेक इंजीनियर्स	ग्वालियर
सचदेव ग्रुप	इंदौर
सेलेक्ट बिल्डर	शाहडोल
घनाराम इंफ्रास्ट्रक्चर	सागर

उद्योग विभाग

कंपनी	संभाग
सेकलिंक	भोपाल
ओनिक्स	जबलपुर
बाल्फोर	इंदौर
पुनर्जागरण	नर्मदापुरम
ट्राइडेंट लिमिटेड	भोपाल
श्री सीमेंट लिमिटेड	इंदौर

पर्यटन विभाग

कंपनी	संभाग
स्वर्णमुखी रिक्रिएशन	इंदौर
फ्लयोला इंडिया	इंदौर
अमलतास होटल्स	इंदौर
अध्यात्म ग्राम ऑकारेश्वर	इंदौर
ओमनी ग्रुप	इंदौर
शैंकी एस	इंदौर
फील्डे रूम्स	भोपाल
ट्रेजर ग्रुप	भोपाल

प्रदेश में बिजली उत्पादन 31 हजार मेगावाट, 30 फीसदी ग्रीन एनर्जी से

मप्र में वर्तमान में 31 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता है, जिसमें से 30 फीसदी हरित ऊर्जा से मिलती है। जीआईएस में प्रदेश की टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिक रिन्युएबल एनर्जी पॉलिसी के कारण नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में भारी निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। सरकार के ठोस प्रयासों से मप्र हरित ऊर्जा हब के रूप में उभर रहा है। वर्तमान में राज्य में 5 बड़ी सौर परियोजनाएं काम कर रही।

लोकसभा के झटकों से सबक...वर्चस्व कायम करने में जुटी भाजपा

भारतीय जनता पार्टी वर्चस्व कायम करने में जुटी हुई है। आज राष्ट्रीय तनतांत्रिक गठबंधन यानी राजग शासित राज्यों की संख्या 20 है। हाल ही में दिल्ली चुनाव में बीजेपी ने जीत का परचम लहराया। लोकसभा चुनाव के झटकों के बाद बीजेपी की जीत में और उछाल आया है। इसके चलते भाजपा साफ राजनीतिक संदेश दे रही है कि विभाजित विपक्ष के लिए उसे रोक पाना असंभव सा है।

यदि एन. बीरेन सिंह जातीय हिंसा की आग में जलते मणिपुर को संभालने में नाकामी के चलते मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने को मजबूर नहीं हुए होते तो दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार की ताजपोशी के साथ ही भाजपा और उसकी अगुआई वाला राजग देश की सत्ता-राजनीति में वर्चस्व का अपना ही कीर्तिमान और बेहतर कर चुका होता। तब देश के 19 राज्यों और दो केंद्रशासित प्रदेशों में राजग का शासन होता। इससे पहले 2018 में राजग का 20 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में शासन था। एन. बीरेन सिंह के इस्तीफे के बावजूद राजग शासित राज्यों की संख्या 20 है। 15 राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों में तो भाजपा के ही मुख्यमंत्री हैं, शेष में राजग की सरकार है। वैसे भाजपा विधायक दल में नए नेता के नाम पर सहमति न बन पाने के चलते मणिपुर में विधानसभा निलंबित कर राष्ट्रपति शासन लगाया गया है यानी नई सरकार बनने का विकल्प खुला हुआ है। बेशक 27 साल बाद देश की राजधानी में सत्ता की वापसी का जश्न भाजपा के लिए नए सत्ता-कीर्तिमान के साथ और भी खास बन जाता, लेकिन 18 राज्यों और दो केंद्रशासित प्रदेशों में सरकार होना भी वर्तमान राजनीति में कम बड़ी उपलब्धि नहीं। इसका अर्थ यह भी है कि पिछले साल लोकसभा चुनाव में लगे झटके से भाजपा उबर चुकी है। राज्यों की राजनीति की दृष्टि से 2019 के बाद का समय भाजपा और राजग के लिए उतार-चढ़ाव वाला रहा। 2019 के चुनाव के बाद महाराष्ट्र में पुराने मित्र शिवसेना से मुख्यमंत्री पद को लेकर हुई तकरार के चलते सत्ता हाथ से निकल गई तो बाद में बिहार में नीतीश कुमार भी पाला बदल कर राजद-कांग्रेस के महागठबंधन में चले गए। 2023 के अंत में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जीत हासिल कर भाजपा ने सबको चौंका दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने महाराष्ट्र और बिहार, दोनों में अपने समीकरण दुरुस्त कर लिए। महाराष्ट्र में शिवसेना में दलबदल के जरिये सत्ता में वापसी कर ली तो बिहार में भी नीतीश कुमार अचानक पाला बदल कर फिर राजग में आ गए। इसके बावजूद लोकसभा चुनाव में झटके

से भाजपा नहीं बच सकी। बिहार में तो ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, पर महाराष्ट्र के साथ ही उत्तर प्रदेश में जबरदस्त झटका लगा। अगर प्रधानमंत्री मोदी पुराने नाराज दोस्तों नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को चुनाव पूर्व ही राजग में न ले आए होते तो सत्ता की हैट्रिक मुश्किल हो जाती, क्योंकि अपने दम पर तो भाजपा बहुमत का आंकड़ा पाने में चूक ही गई थी। भाजपा के ग्राफ में सबसे बड़ा उछाल लोकसभा चुनाव के झटके के बाद ही आया। हरियाणा में लगातार दूसरी बार सरकार बनाने के बावजूद लोकसभा चुनाव में भाजपा 10 में से पांच सीटें हार गई थी, मगर पिछले विधानसभा चुनाव में उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए सत्ता की हैट्रिक लगाई। महाराष्ट्र में तो कमाल ही हो गया। लोकसभा चुनाव में आइएनडीआइए के स्थानीय स्वरूप एमवीए की भारी बढ़त के बावजूद विधानसभा चुनाव में भाजपा और उसके नेतृत्व में महायुति ने एकतरफा जीत हासिल की। इसके बाद दिल्ली में खुद को अजेय समझने वाले अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को सत्ता से बेदखल कर भाजपा ने साफ राजनीतिक संदेश दे दिया है कि उसे रोक पाना, खासकर विभाजित विपक्ष के लिए तो असंभव सा है। पिछले दो विधानसभा चुनावों के मद्देनजर तो दिल्ली में मुकाबला ही नहीं माना जा रहा था, लेकिन भाजपा ने ऐसी चुनावी बिसात बिछाई कि आप से 40 सीटें छीन कर बहुमत से भी 12 ज्यादा 48 तक जा पहुंची। बेशक 21वीं शताब्दी में पहली बार दिल्ली में भाजपा सरकार बनी है, लेकिन इस जीत का एक और बड़ा राजनीतिक फलितार्थ यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उसे अकेले दम पर बहुमत से वंचित कर देने वाला विपक्षी गठबंधन बिखराव के कगार पर पहुंच गया है। लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ी कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में अकेले ताल ठोकी तो विपक्षी गठबंधन के तृणमूल, सपा, शिवसेना-यूबीटी और शरद पवार की राकांपा जैसे घटक दलों ने अरविंद केजरीवाल की आप का समर्थन किया। ऐसे में विपक्षी गठबंधन में सब कुछ सामान्य नहीं रह गया है। इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव हैं। वहां राजद और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर तनातनी के संकेत हैं। सबसे महत्वपूर्ण होंगे अगले साल होने वाले बंगाल विधानसभा चुनाव। आईएनडीआईए में होते हुए भी तृणमूल ने बंगाल में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ा तो अब विधानसभा चुनाव भी अकेले ही लड़ने का एलान कर दिया है। दिल्ली में कांग्रेस भले ही लगातार तीसरी बार खाता खोलने में नाकाम रही, पर उसने आप की सत्ता से विदाई में निर्णायक भूमिका निभाई। इससे कांग्रेस ही नहीं, भाजपा भी उत्साहित है। अगर बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल अकेले लड़ने के फैसले पर अडिग रहती है तो कांग्रेस-वाम मोर्चा गठबंधन की चुनावी रण में मौजूदगी भाजपा के लिए मददगार हो सकती है। बार-बार हुंकार भरने के बावजूद भाजपा बंगाल में मुख्य विपक्षी दल बनने तक ही पहुंच पाई है। सत्ता अभी भी बहुत दूर नजर आती है, लेकिन दिल्ली के चुनाव परिणाम बताते हैं कि समीकरण बदलते देर नहीं लगती। लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा सिर्फ मोदी की लोकप्रियता पर ही चुनाव नहीं लड़ती आई है। उसने स्थानीय नेतृत्व को भी चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका देते हुए स्थानीय मुद्दों को धार देने का जो प्रयोग किया है, वह महाराष्ट्र से दिल्ली तक वांछित परिणाम देने वाला साबित हुआ है।

महाकुंभ का संदेश-भीड़ नियंत्रण के उपायों पर हो मंथन

45 दिनों तक चले प्रयागराज महाकुंभ का समापन हुआ। इस अवधि में 65 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। 144 साल बाद आए इस विशेष महाकुंभ का साक्षी बनने के लिए देश दुनिया से लोग प्रयागराज आए। महाकुंभ ने जहां आस्था का नया शिखर स्पर्श किया वहीं यह भी बताया कि भविष्य में ऐसे आयोजनों में लोग और बढ़चढ़कर हिस्सा लेंगे।

13 जनवरी 2025 को पौष पूर्णिमा के दिन से शुरू हुआ महाकुंभ शिवरात्रि को संपन्न हो गया। इस बार महाकुंभ में संगम पर जिस तरह अपार जन समूह ने स्नानकर अपने को धन्य किया, उसकी अपेक्षा किसी को नहीं थी। उत्तर प्रदेश सरकार का आकलन है कि 65 करोड़ से अधिक लोग महाकुंभ में सम्मिलित हुए। इतने बड़े जनसमूह का 45 दिनों की अवधि में एक स्थान पर आकर एकत्रित होने से जहां एक कीर्तिमान स्थापित हुआ, वहीं इस बात को भी बल मिला कि भारत के लोगों को उस दैवीय शक्ति पर अगाध श्रद्धा है, जो मनुष्य को प्रेरित करती है कि वह ऐसे अवसरों पर आगे आकर जीवन के रहस्यों से परिचित हो और अपनी आध्यात्मिक भूख शांत करे। यह स्वाभाविक ही है कि लोग कुंभ को दैवीय कृपा का आशीर्वाद मानते हैं। भारतीय संस्कृति में कुंभ का विशेष महत्व है। इसका उल्लेख हमारे शास्त्रों में भी मिलता है। कुंभ मेले का आयोजन हिंदू धर्म की सबसे प्राचीन परंपराओं में से एक है। कुंभ के आयोजन के पीछे पौराणिक और धार्मिक कारण ही नहीं, खगोलीय कारण भी हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया। इस मंथन के समय अमृत का एक कुंभ यानी कलश निकला। यह असुरों के हाथ लग गया, जिसे बचाने देवता आगे आए। इसी क्रम में अमृत की कुछ बूंदें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नाशिक में गिरीं। इन चारों स्थानों को पवित्र मानकर यहां नदियों के तट पर कुंभ मेले का आयोजन होने लगा। कुंभ का भव्य आयोजन नाशिक, उज्जैन और हरिद्वार में भी होता है, लेकिन तीर्थराज प्रयागराज के कुंभ की महत्ता कहीं अधिक है। इसका एक कारण यह है कि प्रयागराज में गंगा, यमुना के साथ अदृश्य सरस्वती का मिलन होता है। भले ही सरस्वती अदृश्य हो, लेकिन उसके अस्तित्व के प्रति भारतीयों की आज भी दृढ़ आस्था है। यही आस्था करोड़ों लोगों को कुंभ की ओर आकर्षित करती है और बिना किसी बुलावे के। कुंभ साधु-संतों और भक्तों के मिलन का एक बड़ा केंद्र बनता है। कुंभ आध्यात्मिक ज्ञान का केंद्र ही नहीं बनता, बल्कि वह सांस्कृतिक आदान-प्रदान का माध्यम भी बनता है। इसके अतिरिक्त वह सामाजिक समरसता का भी परिचायक होता है। आजादी के पहले भी संत-महात्माओं के साथ कुंभ पर जन समूह एकत्रित होता था, लेकिन जैसे-जैसे आवागमन की सुविधाएं बढ़ीं, लोगों ने कुंभ में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेना शुरू किया। यहां आने वालों के बीच कहीं कोई भेद नहीं रहता। इस बार का कुंभ खगोलीय विशिष्टताओं के कारण महाकुंभ

कहलाया और इसीलिए इसमें देश के हर कोने और यहां तक कि दुनिया के अनेक हिस्सों से लोग आए। उत्तर प्रदेश सरकार का आकलन था कि महाकुंभ में लगभग 40 करोड़ लोग आएंगे, लेकिन इस अनुमान से कहीं अधिक 65 करोड़ से ज्यादा लोग प्रयागराज आए। बहुत से लोगों ने इस कौतूहल के कारण भी हिस्सा लिया कि आखिर इतना बड़ा जनसमूह महाकुंभ क्यों पहुंच रहा है? जहां प्रधानमंत्री मोदी और अन्य अनेक लोग महाकुंभ को भारतीय एकता का कुंभ कह रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसकी विवेचना इस तरह कर रहे हैं कि यह प्रकृति का दर्शन है और कुंभ जाकर हम पृथ्वी पर जीवनदायी सबसे अहम स्रोत-जल का नमन करते हैं। हिमालय की बर्फ हो या मानसून की वर्षा, प्रकृति ने भारतीय उपमहाद्वीप को जल से विभूषित किया है। कुंभ जल स्रोतों की महत्ता का भी परिचायक है। हम भारतीयों को यह याद रखना होगा कि जल स्रोतों का शुद्ध रहना बहुत जरूरी है। आज हमारी नदियां प्रदूषित हो चुकी हैं। महाकुंभ में तीर्थयात्रियों को प्रदूषित जल में स्नान न करना पड़े, इसके लिए प्रशासन ने कड़े जतन किए। इस पर कुछ राजनीति भी हुई कि स्नान के आखिरी दिनों में जल प्रदूषित हो रहा था। कई लोगों ने इसे मुद्दा भी बनाया, पर उनकी आवाज को आस्था के सैलाब ने अनसुनी कर दी। अब जब महाकुंभ समाप्त हो गया है और करोड़ों लोगों ने जिस जल को नमन कर प्रकृति का आशीर्वाद लिया, उसे गंगा-यमुना के साथ अन्य नदियों को शुद्ध रखने की जिम्मेदारी उठानी होगी।

अमर्यादित कूटनीति, यूक्रेन की अनदेखी,ट्रंप ने थोपी मनमर्जी

व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच जैसी तीखी तकरार मीडिया और विशेष रूप से टीवी कैमरों के सामने हुई, उसकी मिसाल मिलना कठिन है। इस तकरार को अमर्यादित कूटनीति का शर्मनाक नमूना ही कहा जाएगा। व्हाइट हाउस में जो कुछ हुआ और खासकर अमेरिकी राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति ने यूक्रेन के राष्ट्रपति को जिस तरह खरी-खोटी सुनाई, वह कल्पना से परे है। अमेरिकी राष्ट्रपति के सहयोगी भले ही यूक्रेन के राष्ट्रपति से माफी की मांग कर रहे हों, लेकिन सच यह है कि अपमान यूक्रेन राष्ट्रपति का हुआ। उन्हें न केवल व्हाइट हाइस का दरवाजा दिखा दिया गया, बल्कि यह भी कह दिया गया कि यदि उन्हें अमेरिकी शर्तें स्वीकार हों तो वह लौटकर आ सकते हैं। आखिर यह यूक्रेन के हितों की अनदेखी कर उस पर अपनी मनमर्जी थोपना नहीं तो और क्या है? सभी इससे परिचित हैं कि ट्रंप बड़बोले एवं अलग शैली वाले नेता हैं और अपने दूसरे कार्यकाल में वह अमेरिका के साथ दुनिया की समस्याओं को आनन-फानन सुलझाना चाहते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वह अपनी ही चलाएं। जब उन्होंने सबके सामने जेलेंस्की की जायज चिंताओं को भी सुनने-समझने से इन्कार कर दिया और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को मूर्ख तक कह दिया, तब यह अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है कि बंद कमरे में वह अन्य शासनाध्यक्षों के साथ किस तरह पेश आते होंगे? यह ठीक है कि अमेरिका सबसे शक्ति शाली राष्ट्र है, लेकिन उसके राष्ट्रपति का इतना अहंकारी और अक्खड़ होना ठीक नहीं। वैसे तो ट्रंप और जेलेंस्की के बीच बात तब बिगड़ी, जब अमेरिकी उप राष्ट्रपति जेडी वेंस ने दखल दिया, लेकिन चूक यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी हुई। यदि वह खनन समझौते के लिए ट्रंप से मिलने आए थे तो युद्ध विराम के मसले पर चर्चा के पहले उन्हें यह आभास होना चाहिए था कि अमेरिकी राष्ट्रपति का इरादा क्या है? उनका यह इरादा किसी से छिपा नहीं कि वह यूक्रेन को और अधिक सहायता देने के लिए तैयार नहीं। लगता है कि जेलेंस्की अपनी अनुभवहीनता के चलते बिगड़ती बात संभाल नहीं सके। उन्हें इससे भली तरह परिचित होना चाहिए था कि ट्रंप रूस-यूक्रेन टकराव रोकने की जल्दी में हैं और वह इस युद्ध के लिए रूस से ज्यादा यूक्रेन के रवैये को जिम्मेदार ठहराते चले आ रहे हैं। निःसंदेह इसी के साथ ट्रंप और उनके सहयोगियों को भी यह समझना चाहिए कि यदि जेलेंस्की यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी के साथ रूस से शांति समझौता चाह रहे थे तो इसमें गलत कुछ भी नहीं। ट्रंप कुछ भी कहें, हमलावर तो रूस ही है। रूस-यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप के रवैये से यह स्पष्ट है कि युद्ध के मोर्चे पर किसी तरह डटे जेलेंस्की की कठिनाई और यूरोप की चिंताएं बढ़ने वाली हैं।

जीआईएस में बोले शिवराज- आठ फूड पार्क, 5 एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर, 2 मेगा फूड व 2 मसाला पार्क

खाद्य प्र-संस्करण के क्षेत्र में प्रदेश में निवेश की अपार संभावनाएं निवेश प्रोत्साहन के लिए मध्यप्रदेश में सिंगल विंडो प्रणाली लागू

भोपाल। जागत गांव हमार

कृषि, उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण विभाग द्वारा इनवेस्ट मध्यप्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2025 में आयोजित सीड टू सेल्फ इन लांचिंग इन्वेस्टमेंट अपार्चुनिटी इन एमपी एग्री फूड एण्ड डेयरी सेक्टर पर आयोजित सत्र में केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। मध्यप्रदेश निवेश के लिए आवश्यक अधोसंरचना के साथ एक लाख हैक्टेयर का लैंड बैंक रखने वाला देश का पहला राज्य है। उन्होंने कहा कि उद्यानिकी फसलों के अंतर्गत टमाटर, मटर, प्याज, लहसुन, मिर्च, गेहूं और चावल उत्पादन में देश अग्रणी है। उन्होंने कहा कि कृषि-उद्यानिकी उत्पादन की प्रचुर मात्रा में उत्पादन से किसान को फसल का भरपूर दाम नहीं मिल पाता है। इसलिए आवश्यक है कि प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा दिया जाए। इससे फसलों का वैल्यू एडीशन होगा। किसान और उत्पादक इकाई, दोनों लाभान्वित होंगे। इसी तरह भारत पूरी दुनिया में फूड प्रोसेसिंग के लिये वर्ल्ड लीडर बन सकता है। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय कृषि मंत्रालय फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए बीज और पौध की नवीन किस्म विकसित करवा रहा है। देश के कृषि उत्पादन को विदेशों में बेहतर मांग मिल सके, इसके लिए भारत सरकार द्वारा चावल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी शून्य कर दी है। साथ ही ऑइल पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दी है। इसका लाभ देश की फूड प्रोसेसिंग इकाइयों को मिलेगा। उन्होंने सभी निवेशकों को मध्यप्रदेश में निवेश के लिए भरपूर सहयोग का आश्वासन भी दिया। वहीं उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाह ने कहा कि मप्र अपनी समृद्ध कृषि, उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण क्षमताओं के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। प्रदेश के उद्यानिकी उत्पादों ने देश में अलग पहचान बनायी है। प्रदेश के 27 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में उद्यानिकी फसलों का उत्पादन किया जा रहा है। इसे आगामी 5 वर्षों में बढ़ाकर 32 लाख हेक्टेयर तथा उत्पादन 400 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 500 लाख टन करने का लक्ष्य रखा गया है। देश के कुल जैविक उत्पादन में मध्यप्रदेश की भागीदारी 40 प्रतिशत है। प्रदेश का रियावन लहसुन और सुंदरजा आम विश्व बाजार में अपनी अलग पहचान रखता है।

किसानों की आय में इजाफा सरकार का संकल्प

कुशवाह ने कहा कि मप्र सरकार ने कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में विशेष निवेश योजनाओं को लागू करते हुए 'एक जिला-एक उत्पाद' पहल के तहत 52 जिलों की विशिष्ट फसलें चिन्हित की हैं। सरकार द्वारा बनायी गयी नवीन निवेश नीतियों को निवेशकों के अनुकूल बनाया गया है। साथ ही इन नीतियों के निर्धारण के लिए निवेशकों के सुझाव भी राज्य सरकार द्वारा खुले मन से आमंत्रित किए गए हैं। निवेश प्रोत्साहन के लिए सिंगल विंडो प्रणाली रखी गयी है, जिसमें भूमि का आवंटन एवं सभी प्रकार की अनुमतियां कम से कम समय में मिल सकेंगी। किसानों की आय, रोजगार, निवेश तथा निर्यात में वृद्धि राज्य सरकार का संकल्प है।

विस्तृत चर्चा करने की आवश्यकता

कृषि उत्पादन आयुक्त मोहम्मद सुलेमान ने कहा कि फसल को खेत से बाजार तक पहुंचाने और उसे वाजिब दाम उपलब्ध कराने पर विस्तृत चर्चा करने की आवश्यकता है। उन्होंने मध्यप्रदेश में कृषि, पशुपालन एवं उद्यानिकी के महत्व और उनके निर्यात संभावनाओं पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में राज्य के कृषि, खाद्य प्र-संस्करण एवं डेयरी क्षेत्रों में निवेश के नए अवसरों पर व्यापक चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में विभिन्न विशेषज्ञों ने किसानों, उद्यमियों और निवेशकों के लिए नवाचार, तकनीकी प्रगति एवं सरकारी नीतियों के महत्व पर रोशनी डाली।

क्लस्टर चयनित किए गए

प्रमुख सचिव अनुपम राजन ने कहा कि प्रदेश में निवेश का बेहतर माहौल तैयार किया जा रहा है। राज्य की सशक्त अधोसंरचना के अंतर्गत 8 फूड पार्क, 2 मेगा फूड पार्क, 5 कृषि प्र-संस्करण क्लस्टर एवं एक लॉजिस्टिक पार्क निवेशकों को उत्कृष्ट अवसर प्रदान कर रहे हैं। इसके साथ ही, सिंगल विंडो प्रणाली के माध्यम से भूमि आवंटन एवं सभी प्रकार की अनुमतियाँ शीघ्र उपलब्ध कराई जा रही हैं। मिनी योजनाओं से लेकर उन्नत फ्रोजन लॉजिस्टिक अधोसंरचना तक के अनेक कदम उठाये जा रहे हैं, जिससे किसानों की आय, रोजगार एवं निर्यात में वृद्धि सुनिश्चित होगी। उद्यानिकी के समग्र विकास एवं वैश्विक स्तर पर वृद्धि करने के लिये भारत सरकार के सहयोग से विशेष फसल आधारित क्लस्टर का चयन किया गया है। जैसे निमाड़ में मिर्च, गुना-राजगढ़ में धनिया, बुंदेलखण्ड में अदरक, बघेलखण्ड में हल्दी, बुरहानपुर में केला, मटर, जबलपुर, देवास और इंदौर में आलू के क्लस्टर चयनित किए गए हैं।

नये उद्यमी योजना का उठाएं लाभ

केन्द्रीय सचिव कृषि सुब्रत गुप्ता ने कहा कि फूड प्रोसेसिंग भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। हमारे घरों में फूड प्रोसेसिंग का लगातार उपयोग होता है। बदलते परिवेश में रेडी-टू-फूड और रेडी-टू-ईट फूड की मांग लगातार बढ़ रही है। इससे भारत दुनिया में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर सकता है। केन्द्र सरकार द्वारा फूड प्रोसेसिंग को प्रोत्साहित करने के लिए 1000 करोड़ रुपऐ का प्रावधान किया गया है। नए उद्यमी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

कृषि उपज मंडियों की सुदृढ़ श्रंखला

आयुक्त उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण प्रीति मैथिल ने कहा कि मध्यप्रदेश में वह सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध हैं, जिनकी जरूरत नई फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना के लिए होती है। मध्यप्रदेश मसाला फसलों के उत्पादन में देश में प्रथम, फल उत्पादन में द्वितीय और दुग्ध उत्पादन में तृतीय स्थान पर है। प्रदेश में 11 एग्रो क्लाइमेटिक जोन हैं। परिवहन के लिए 700 रेलवे स्टेशन, 60 फ्लाइट्स तथा 9 इनलैंड पोर्ट स्थित हैं। मध्यप्रदेश में कृषि विपणन के लिए कृषि उपज मंडियों की सुदृढ़ श्रंखला है। इनमें एक लाख करोड़ मीट्रिक टन कृषि उत्पादन का विक्रय प्रतिवर्ष किया जाता है। वर्तमान में प्रदेश में 4 हजार फूड प्रोसेसिंग यूनिट कार्य कर रही हैं।

उत्पाद को बाजार तक पहुंचाने की प्रक्रिया

पहली पैनल फ्रॉम फार्म-टू-मार्केट में एस गणेश कुमार (एग्री बिजनेस आईटीसी लिमिटेड) ने कृषि, डेयरी और बागवानी के महत्व के साथ-साथ मूल्य श्रृंखला को बढ़ाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण के अवसरों पर विचार-विमर्श किया। उन्होंने किसानों द्वारा उत्पाद को बाजार तक पहुंचाने की प्रक्रिया, परिवहन चुनौतियां के उपायों पर जोर दिया।

बाजार में नई संभावनाएं

तीसरी पैनल मार्केट ट्रेण्ड्स एण्ड कंजूमर प्रिफरेंसेस में खाद्य प्र-संस्करण उद्योग में उपभोक्ता प्राथमिकताओं में परिवर्तन जैसे कि जैविक, ग्लूटेन-फ्री एवं प्लांट-बेस्ड उत्पादों के उदय एवं स्थिरता के महत्व को रेखांकित किया गया। यह भी बताया गया कि नवाचार एवं उत्पाद विविधीकरण से बाजार में नई संभावनाएं उत्पन्न हो रही हैं। चौथी पैनल फ्रॉम फार्म-टू-वेलनेस में मोहित मल्होतरा ने औषधीय एवं न्यूट्रास्यूटिकल फसलों के क्षेत्र में बढ़ती मांग, हर्बल सप्लीमेंट्स तथा फंक्शनल फूड्स के बाजार एवं पर्यावरणीय प्रभावों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि किस तरह से मूल्य वर्धन और उत्पाद विकास से इस क्षेत्र में उल्लेखनीय अवसर उत्पन्न हो रहे हैं।

सशक्त बनाने पर जोर दिया

पांचवीं पैनल फूड प्रोसेसिंग ऑपर्चुनिटीज इन बैंक वॉटर एण्ड फारवर्ड लिंकेज में अनुकूल जोशी ने आपूर्ति श्रृंखला में पारदर्शिता, गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं डिजिटल प्लेटफार्म द्वारा लिंक को मजबूत बनाने के उपाय सुझाए। छठी पैनल इम्पॉवरिंग फार्मर्स द फ्यूचर ऑफ एग्री-फायनेंस में अनिल सिन्हा ने कम ब्याज दर, माइक्रोफाइनेंस, क्रेडिट कार्ड्स और डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर जोर दिया। उन्होंने विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं वित्तीय साक्षरता के महत्व को भी रेखांकित किया।

टिकाऊ प्रथाओं पर जोर

अंतिम पैनल डॉ. मीनश शाह ने डेयरी सेक्टर में तकनीकी नवाचार, स्वचालन एवं डिजिटल सप्लाई चेन के जरिए निवेश एवं लाभप्रदता बढ़ाने के अवसरों पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने जैविक डेयरी, लैक्टोज-फ्री विकल्प एवं टिकाऊ प्रथाओं की भूमिका पर विशेष ध्यान आकर्षित किया। कार्यक्रम ने मध्यप्रदेश में कृषि, खाद्य प्र-संस्करण एवं डेयरी क्षेत्रों के विकास के लिए निवेश के नए आयाम खोलते हुए राज्य की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देने की दिशा में कदम बढ़ाने का संदेश दिया।

-उद्यानिकी मंत्री कुशवाह ने कहा- उत्पादों को बेहतर मार्केट उपलब्ध कराने सरकार संकल्पित

उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाह ने कहा है कि कृषि एवं उद्यानिकी उत्पाद को बेहतर मार्केट उपलब्ध हो सके, इसके लिये राज्य सरकार कृत-संकल्पित है। प्रदेश में खाद्य प्र-संस्करण इकाइयों की अधिकाधिक स्थापना के लिये भोपाल में आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में बड़ी संख्या में इन्वेस्टर्स द्वारा रुचि ली गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार-भारत सरकार के साथ मिलकर उत्पादकों को बेहतर बाजार उपलब्ध करायेगी। उन्होंने यह बात भोपाल हाट बाजार में विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित कार्यशाला और राष्ट्रीय प्रदर्शनी के शुभारंभ अवसर पर कही।

इस अवसर पर कमिश्नर उद्यानिकी प्रीति मैथिल, सहायक कृषि विपणन सलाहकार भारत सरकार अक्षय याकूब सहित किसान भाई, एफपीओ के सदस्य उपस्थित थे। मंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश उद्यानिकी और कृषि फसलों के उत्पादन में देश में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रदेश में खाद्य प्र-संस्करण इकाइयों की स्थापना के लिये राज्य शासन द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश के बाहर के खाद्य प्र-संस्करण के क्षेत्र में कार्य करने वाले उद्यमियों को राज्य शासन उद्यम निवेश नीतियों के तहत पूर्ण सहयोग और समर्थन दिया जाएगा। उन्होंने उद्यानिकी फसलों के संबंध में अपने अनुभव भी साझा किए। सहायक कृषि विपणन सलाहकार भारत सरकार अक्षय याकूब ने बताया कि कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य कृषि विपणन से जुड़े किसानों को आधुनिक विपणन तकनीकों से अवगत कराना, सहकारी संस्थानों की भूमिका, एग्री-बिजनेस के अवसरों को बढ़ावा देना तथा ग्रामीण एवं शहरी बाजारों के बीच तालमेल स्थापित करना शामिल है। इस कार्यक्रम में विभिन्न विशेषज्ञ एगमार्क सर्टिफिकेशन, आधुनिक विपणन प्रणाली, मूल्य संवर्धन प्र-संस्करण भंडारण, निर्यात तथा ई-बाजार जैसे पहलुओं पर विस्तृत व्याख्यान दिये गये। इसके अलावा कार्यशाला में किसानों को प्रशिक्षण देकर उन्हें नवीनतम कृषि विपणन नीतियों और योजनाओं से अवगत कराया गया।

प्रतिभा को सम्मान : डॉ. सत्येंद्र को मिला कृषि सम्मान पुरस्कार

लहार। जागत गांव हमार

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के अधीन संचालित कृषि विज्ञान केंद्र लहार (भिंड) के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख प्रतिष्ठित कृषि विज्ञानी डॉ. सत्येंद्र पाल सिंह को पिछले 30 वर्षों से अधिक समय से कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से किसानों को ग्रामीण स्तर पर वैज्ञानिक-तकनीकी द्वारा किए गए कार्यों के योगदान के लिए दिल्ली प्रेस समूह द्वारा प्रतिष्ठित फॉर्म फूड कृषि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

उनको यह पुरस्कार गत दिवस रविंद्र भवन, भोपाल के सभागार में आयोजित पुरस्कार समारोह में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रीगण विश्वास सारंग, गौतम टेंटवाल, दिल्ली प्रेस के कार्यकारी प्रकाशक अनंतनाग की उपस्थिति में पदमश्री उमाशंकर पांडे एवं अन्य

अथितियों द्वारा प्रदान किया गया है। डॉ. सत्येंद्र पाल सिंह पिछले तीन दशकों से अधिक समय से कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से तकनीकी के प्रचार-प्रसार, फार्मिक सिस्टम रिसर्च एवं नवाचारों के द्वारा किसानों को सेवाएं देकर उनको लाभान्वित कर रहे हैं। वह उप्र के कृषि विज्ञान केंद्र एटा, आगरा और मप्र के मुरैना, शिवपुरी में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वर्तमान में वह मध्य प्रदेश के भिंड जिले के कृषि विज्ञान केंद्र पर प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख के पद पर पदस्थ हैं। डॉक्टर सत्येंद्र द्वारा किसानों को अनवरत रूप से दी जा रही सेवा का सम्मान करते हुए दिल्ली प्रेस समूह द्वारा उनको बेस्ट रिसर्च इन फार्मिंग सिस्टम कैटेगरी में उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 2025 का राज्य स्तरीय (मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़) फॉर्म एवं फूड कृषि सम्मान अवार्ड से सम्मानित किया गया है।

-मुख्यमंत्री मोहन ने कहा-गेहूं पर 175 रुपए क्विंटल मिलेगा बोनस

-बालाघाट के खिलाड़ियों को मिली हॉकी एस्ट्रो टर्फ की सौगात

किसानों को धान पर 4 हजार रु. हेक्टेयर मिलेगा अतिरिक्त लाभ

भोपाल।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बालाघाट के किसान सम्मेलन में किसानों को अभूतपूर्व सौगात देते हुए कहा कि अब प्रदेश में धान उत्पादक किसानों को 4 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गेहूं उत्पादक किसानों को भी प्रति क्विंटल 175 रुपए अतिरिक्त बोनस राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मूल्य संवर्धन योजना (प्राइस सपोर्ट स्कीम) अंतर्गत वर्ष 2024 में 6.69 लाख किसानों द्वारा 12.2 लाख हेक्टेयर रकबे में उत्पादित धान का विक्रय किया गया है। धान उत्पादक किसानों को मुख्यमंत्री कृषक प्रोन्नति योजना में प्रति हेक्टेयर 4000 रुपए का लाभ मिलेगा। इससे प्रदेश के किसानों को 488 करोड़ का अतिरिक्त लाभ होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि गेहूं उत्पादक किसानों को भी समर्थन मूल्य 2425 रुपए के अतिरिक्त 175 रुपए प्रति क्विंटल की बोनस राशि दी जाएगी। इस प्रकार गेहूं के उपार्जन पर प्रति क्विंटल 2600 रुपए की राशि मिलेगी। इस वर्ष प्रदेश में 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन अनुमानित है। प्रदेश के किसानों को 175 रुपए प्रति क्विंटल बोनस के रूप में मिलने से लगभग 1400 करोड़ की अतिरिक्त राशि का लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए संकल्पबद्ध होकर निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक लाख सरकारी पदों पर भर्ती की जा रही है। आने वाले 5 वर्षों में 2 लाख 70 हजार पदों पर विभिन्न सेक्टर में रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। हमारी सरकार वर्ष 2028 तक सरकार 70 प्रतिशत युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्धता पूर्वक कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रदेश में चल रही योजनाएं यथावत चलती रहेंगी। कोई भी योजना बंद नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि प्रदेश सभी क्षेत्रों में लगातार नंबर वन पर बना रहे।

- पांच वर्षों में 2 लाख 70 हजार युवाओं को मिलेगी नौकरियां
- 326 करोड़ 60 लाख के कार्यों का भूमि-पूजन और लोकार्पण
- जीआईएस-भोपाल में मिला प्रदेश को विकास का आशीर्वाद

सबका होगा पक्का मकान

मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में निरंतर आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से 5वें नंबर पर आ गई है और अब हम चौथे नंबर पर आने के लिए अग्रसर है। सबसे तेज गति से विकास करने वाला देश भारत है, और यह प्रसन्नता की बात है कि वर्तमान में सर्वाधिक जीएसडीपी ग्रोथ रेट 13 प्रतिशत मध्यप्रदेश की है। सीएम ने कलेक्टर को निर्देशित किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण का लाभ सभी पात्र हितग्राहियों को दिलाना सुनिश्चित किया जाए। कोई भी व्यक्ति पक्के मकान के बगैर नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री ने बालाघाट को खनिजों का सम्राट जिला बताते हुए कहा कि यह प्राकृतिक और खनिज संपदा से समृद्ध जिला है। तांबा और मैंगनीज यहां भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। चित्रोर के चावल की खुशबू सभी ओर व्याप्त है।

मध्यप्रदेश फार्मर आईडी जनरेट करने में प्रथम स्थान पर

-अब तक 56 लाख 82 हजार 234 आईडी जनरेट हो चुकी

भोपाल। जागत गांव हमार

भारत सरकार की एग्रीस्टैक परियोजना के तहत मध्यप्रदेश में किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में फार्मर रजिस्ट्री की शुरुआत की गई है। इसमें प्रत्येक किसान के लिए एक यूनिक फार्मर आईडी बनाया जा रहा है। प्रदेश में कुल 95 लाख 18 हजार 752 प्रधानमंत्री किसान योजना के हितग्राही हैं। इसमें अब तक 56 लाख 85 हजार 337 कुल 59.73 प्रतिशत किसानों ने अपना पंजीयन करा लिया है। अब तक 56 लाख 82 हजार 234 आईडी भी जनरेट हो चुकी है। फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से किसानों का एक डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। इससे किसानों को आसान ऋण कम्प्यूटरीकृत प्रक्रिया माध्यम से प्राप्त हो सकेगा। अन्य योजनाओं के लिये भूमि, फसल एवं कृषकों की जानकारी का सत्यापन इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जा सकेगा। इसमें भौतिक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। फार्मर रजिस्ट्री नवाचार में जिला कलेक्टरों द्वारा राजस्व अमले एवं कृषकों के सहयोग से कैम्प का आयोजन कर प्रदेश में 57 लाख से अधिक फार्मर आईडी बनाये जा चुके हैं। भारत सरकार की स्पेशल सेन्ट्रल असिसटेंस योजना में प्रदेश को राशि रुपये 297 करोड़ प्राप्त हो रही है। फार्मर रजिस्ट्री के तहत फार्मर आईडी जनरेट करने में मध्यप्रदेश का देश में प्रथम स्थान हैं। गुजरात दूसरे, महाराष्ट्र तीसरे, आंध्रप्रदेश चौथे और उत्तर प्रदेश पांचवे स्थान पर है।

–मध्यप्रदेश के कृषि मंत्री एदल सिंह कंषाना ने कहा

प्रमाणित बीजों से बढ़ाई जा रही फसलों की उत्पादकता

भोपाल। जागत गांव हमार

किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री एदल सिंह कंषाना ने कहा है कि बीज प्रमाणीकरण संस्था का गठन भारत सरकार द्वारा अधिसूचित बीज अधिनियम 1966 की धारा 8 के अन्तर्गत किया गया है। संस्था का मुख्य कार्य निर्धारित मानक के अनुरूप गुणवत्ता के बीजों का प्रमाणीकरण करना है। प्रमाणित बीजों से प्रदेश में फसलों की उत्पादकता बढ़ाई जा रही है। बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा विगत एक वर्ष की अवधि में बीज प्रमाणीकरण का अहम कार्य किया गया। खरीफ-2024 में 1.24 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बीज प्रमाणीकरण के लिए पंजीकृत हुआ। 15 लाख क्विंटल बीज प्रमाणित किया गया। रबी सीजन में 1.07 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बीज प्रमाणीकरण के लिए पंजीकृत हुआ और 21.86 लाख क्विंटल बीज प्रमाणित किया गया। ग्रीष्म-2024 में 9021 हेक्टेयर क्षेत्र बीज प्रमाणीकरण के लिए पंजीकृत हुआ और 85 हजार क्विंटल बीज प्रमाणित किया गया। बीज प्रमाणीकरण संस्था के टैग्स पर 2डी क्यूआर कोड का उपयोग किया जा रहा है। किसी भी एन्ड्रॉयड फोन से इसे स्कैन किया जा सकता है। स्कैन करने पर

प्रमाणित बीज लॉट के लिए जारी प्रमाण-पत्र खुल जाएगा, जिसमें बीज लॉट की समस्त जानकारी उपलब्ध है। फसल, किस्म, लॉट क्रमांक, टैगों की सीरीज, कुल कितने टैग जारी किए गए, पैकिंग साइज, पैकिंग मात्रा, बीज परीक्षण परिणाम, अंकुरण, भौतिक शुद्धता, अन्य फसलों, अन्य पहचान योग्य बीज, खरपतवार, नमी, किस कृषक एवं संस्था द्वारा बीज का उत्पादन किया गया और किस सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी द्वारा पैकिंग एवं टैगिंग की गई, समस्त जानकारी स्कैन के माध्यम से देखी जा सकती है। केन्द्र द्वारा तैयार किए गए साथी पोर्टल पर बीजोत्पादन कार्यक्रम और बीज का ट्रेसेबिलिटी ऑथेन्टिकेशन की जानकारी ली जा सकती है।

आधा एकड़ में अश्वगंधा लगाया, 96 हजार रुपए का हुआ मुनाफा

अक्टूबर माह के आखिरी व नंवबर के पहले सप्ताह में किसान करें बोवनी

अश्वगंधा की उपज के लिएएक एकड़ में करीब 15 हजार रुपए का खर्चा

किसान ने अब छह एकड़ में लगाई फसल आयुर्वेद-यूनानी दवाइयों में इस्तेमाल

सागर। जागत गांव हमार

सागर के युवा किसान परंपरागत खेती छोड़कर अश्वगंधा की औषधीय खेती कर रहे हैं। कारण, ये फसलें नकदी होती हैं, जो कम समय में मोटा मुनाफा दिलाती हैं। अश्वगंधा ऐसी ही औषधीय खेती है। इस बार जागत गांव हमार अपने अंक में सागर जिले के रहली ब्लॉक के ग्राम रजवास के रहने वाले युवा किसान प्रशांत पटेल से मिलवा रहा है। प्रशांत परंपरागत खेती छोड़कर अश्वगंधा की खेती कर रहे हैं। अश्वगंधा की खेती करने की विधि उन्होंने यूट्यूब के वीडियो देखकर सीखी। शुरुआत में 50 डिसमिल जमीन (आधा एकड़) पर अश्वगंधा लगाई, जिसमें उन्होंने 7 से 10 हजार रुपए खर्चा किया और उपज आने पर 96 हजार रुपए का मुनाफा हुआ। मुनाफे की खेती देखकर इस बार युवा किसान ने अपनी 6 एकड़ जमीन में अश्वगंधा की फसल लगाई है।

किसान प्रशांत पटेल सागर जिले के एक छोटे से गांव रजवास में रहते हैं। उन्होंने ग्रेजुएशन किया है। परिवार में शुरू से परंपरागत खेती होती आ रही है। उनका भी बचपन से खेती की तरफ रुझान था। पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने खेती करना शुरू की। उनके पास सात एकड़ जमीन है। साथ में रहली में कियोस्क सेंटर चलाते हैं। खेती करने की शुरुआत में उन्होंने परंपरागत फसलें गेहूं, चना, मसूर की खेती की। लेकिन इन फसलों में लागत और मेहनत ज्यादा लगती है और मुनाफा कम होता है। इस कारण उन्होंने अश्वगंधा की खेती करने का विकल्प चुना। किसान प्रशांत पटेल बताते हैं कि मोबाइल पर यूट्यूब के माध्यम से प्रदेश की मंडियों में फसलों के भाव देखता था। एक दिन नीमच मंडी के भाव देख रहा था तो उसमें अश्वगंधा के भाव सबसे ज्यादा थे। अश्वगंधा की खेती से जुड़े वीडियो खंगाले, उन्हें देखा। वीडियो देखने के बाद अश्वगंधा की खेती करने का मन बनाया। खेती करने के तरीकों और विधि के वीडियो भी यूट्यूब पर देखे।

अश्वगंधा की खेती ऐसे करें किसान

किसान प्रशांत ने बताया कि सोयाबीन की फसल आने के बाद खेत खाली हो जाता है। खेत खाली होने के बाद दो बार उसकी गहरी जुताई कराएं। करीब 15 दिन तक खेत को खाली छोड़ दें। मिट्टी को भुरभुरी बना दें। अक्टूबर माह के आखिरी और नंवबर के पहले सप्ताह में बोवनी करें। अश्वगंधा की बोवनी दो विधियों से की जा सकती है। पहली बीज का छिड़काव करके और दूसरा नर्सरी तैयार कर बीज को अंकुरित करके पौधों के रूप में रोपे जा सकते हैं। बोवनी से पहले बीज को नीम के पत्तों के काढ़े से उपचारित करें, जिससे फफूंदी आदि से हानि न होने पाए। अश्वगंधा की अच्छी फसल के लिए कतार का फासला 20 से 25 सेमी और पौधे से पौधे का 4-6 सेमी होना चाहिए। बीज 2-3 सेमी से अधिक गहरा नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से निदाई-गुड़ाई भी आसानी से की जा सकती है। एक एकड़ में करीब 7 किलो बीज की जरूरत पड़ती है। यह फसल बोवनी से 160-180 दिनों में तैयार हो जाती है। जिसके बाद फसल की खुदाई कराई जा सकती है।

एक एकड़ में 15 हजार खर्च, मुनाफा 1.50 लाख का

किसान प्रशांत ने बताया कि अश्वगंधा की उपज लेने के लिए किसान को एक एकड़ में करीब 15 हजार रुपए का खर्चा आता है। इसमें खेती तैयार करना, कीटनाशक का छिड़काव, निदाई-गुड़ाई, खुदाई सभी शामिल होते हैं। फसल तैयार होने पर एक एकड़ में करीब 5 से 6 क्विंटल पैदावार होती है। मंडी में अश्वगंधा 35 से 40 हजार रुपए प्रति क्विंटल बिकता है। ऐसे में किसान को एक एकड़ में करीब 1.50 लाख रुपए का मुनाफा होता है। इसके साथ ही अश्वगंधा की जड़ के अलावा तना और बीज भी बिकता है। अश्वगंधा का भूसा 12 से 15 रुपए क्विंटल और बीज करीब 10 हजार रुपए क्विंटल तक बिकता है। किसान अश्वगंधा की खेती करके परंपरागत फसलों की अपेक्षा ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं।

नीमच व मंदसौर की मंडी में बेचने जाते हैं फसल

किसान ने बताया कि अश्वगंधा की उपज सागर जिले में न के बराबर है। पहली बार खेती की है। ऐसे में स्थानीय मंडियों में अश्वगंधा की खरीदी नहीं होती है। उपज बेचने के लिए नीमच और मंदसौर की मंडियों में जाना पड़ता है। इसके लिए पहले हम उपज की ग्रेडिंग करते हैं, फिर उपज लेकर नीमच मंडी जाते हैं। वहां उपज का अच्छा भाव मिलता है। अश्वगंधा की उपज (जड़) में जितना ज्यादा पाउडर होगा, कीमत उतनी अच्छी मिलती है।

दवाइयों में होता है अश्वगंधा का उपयोग

किसान ने बताया कि अश्वगंधा को देशी औषधीय पौधा माना जाता है। यह जंगली फसल (जड़ी-बूटी) है। इसका भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में काफी उपयोग होता है। इसकी जड़ों से निकलने वाले पाउडर का उपयोग आयुर्वेद और यूनानी दवाइयों को बनाने में किया जाता है। इसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है। परंपरागत फसलों के मुकाबले इसके दाम भी काफी अच्छे मिलते हैं।

200 एकड़ में लगाई अश्वगंधा की फसल

युवा किसान प्रशांत पटेल ने बताया कि सबसे पहले मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से अश्वगंधा की खेती शुरू की। अच्छा मुनाफा हुआ तो गांव और आसपास के युवा किसानों को अश्वगंधा की खेती करने की सलाह दी। उन्हें खेत में लाकर अपनी फसल दिखाई, जिससे वह प्रभावित हुए। नतीजा ग्राम रजवास समेत आसपास के गांवों में करीब 200 एकड़ में इस बार अश्वगंधा की फसल लगाई गई है। यह फसल किसानों के लिए मुनाफे की फसल साबित होगी।

पहले सीएम मोहन फिर पीएम मोदी ने खाते में डाला पैसा

मप्र के 81 लाख किसानों को मिली सम्मान निधि

प्रदेश के किसानों के खातों में 10 किस्तों में कुल 14 हजार 254 करोड़ की राशि भेजी

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्य प्रदेश के किसानों की चांदी हो गई है। दरअसल उनके बैंक खाते में 14 दिन में दूसरी बार 2000 रुपए की किस्त पहुंची है। इससे पहले राज्य के किसानों के खाते में किसान कल्याण के लिए 2000 रुपए भेजे गए थे और फिर पीएम मोदी ने 2000 रुपए की किस्त फिर से भेज दी है। दरअसल, मध्यप्रदेश सरकार भी केंद्र की तरह किसानों को सालाना 6 हजार रुपए देती है। इस तरह राज्य और केंद्र की ओर से किसानों को सालाना 12 हजार रुपए की आर्थिक मदद मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ने बिहार के भागलपुर से रिमोट बटन दबाकर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त के तहत लगभग 9.8 करोड़ से अधिक किसानों को 22 हजार करोड़ से अधिक की राशि ट्रांसफर की। इसमें मध्य प्रदेश के 81.41 लाख लाभार्थी किसान भी हैं, जिनके बैंक खाते 2000 रुपए पहुंचे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 11वीं किस्त के रूप में मध्य प्रदेश के 81.41 लाख किसानों के बैंक खातों में राज्य सरकार की ओर से 2000 रुपए ट्रांसफर किए गए थे। मध्य प्रदेश कृषि विभाग के अनुसार किसानों के खातों में किसान कल्याण योजना तहत 10 किस्तों में कुल 14 हजार 254 करोड़ की राशि भेजी जा चुकी है। साल 2024-25 में योजना के लिए 4 हजार 900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

किसानों को 12 हजार सालाना

राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि सीएम मोहन यादव ने जारी की थी और अब 14 दिन बाद केंद्र सरकार की ओर से पीएम किसान सम्मान निधि के 2000 रुपए बैंक खाते में पहुंच गए हैं। इस तरह से मध्य प्रदेश के 81 लाख से अधिक किसानों को 15 दिन के भीतर दोहरा लाभ मिला है। बता दें कि ने मध्य प्रदेश सरकार राज्य के किसानों को सालाना 6000 रुपए 3 समान किस्तों में देती है। ठीक इसी तरह केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि में भी 6000 रुपए सालाना दिए जाते हैं।

30 लाख अधिक किसानों को मिला पैसा

पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त में 2 हजार करोड़ अतिरिक्त जारी किए हैं, क्योंकि पिछली किस्त की तुलना में लाभार्थी किसानों की संख्या 30 लाख अधिक दर्ज की गई है। 18वीं किस्त के आधिकारिक आंकड़े देखें तो 9.5 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में पैसे पहुंचे थे, लेकिन अब इस बार 19वीं किस्त का पैसा जिन किसानों के खाते में पहुंचा है उनकी आधिकारिक संख्या 9.8 करोड़ से अधिक बताई गई है। इस बार करीब 30 लाख अधिक किसानों के खाते में 19वीं किस्त का पैसा पहुंचा है।

फसल कटाई के बाद उसकी प्रोसेसिंग पर भी जोर

मप्र में एनडीडीबी बढ़ाएगी डेयरी सेक्टर की रफ्तार

भोपाल। जागत गांव हमार

हाल ही में मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया था। नेशनल डेयरी डवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन डॉ. मीनेश शाह भी इसमे शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने मध्य प्रदेश में डेयरी सेक्टर की रफ्तार बढ़ाने पर चर्चा की। साथ ही डेयरी संग पशुपालन को भी प्रदेश में कैसे बढ़ाया जाए और तकनीक शामिल की जाए से जुड़े प्लान को साझा किया। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में फूड प्रोसेसिंग और भविष्य की डेयरी कैसी होगी इस पर बात करने के लिए डेयरी से जुड़े भागीदारों को भी बुलाया गया था। समिट के दौरान फसल कटाई के बाद उसकी प्रोसेसिंग पर भी जोर दिया गया। वहीं डेयरी सेक्टर के लिए भी दूध से ज्यादा से ज्यादा उत्पाद बनाने पर जोर दिया गया। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में डॉ. मीनेश शाह ने कहा कि मध्य प्रदेश में डेयरी से जुड़ी बहुत संभावनाएं हैं। ये भारत के तीसरे सबसे बड़े दूध उत्पादक राज्य के रूप में जाना जाता है। यही वजह है कि एनडीडीबी मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से राज्य के दुग्ध महासंघ और संघों को मजबूत करने का काम करेगी। श्वेत क्रांति 2.0 के तहत सहकारी कवरेज को और बढ़ाया जाएगा। संगठित क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा डेयरी किसानों को लाने का काम किया जाएगा। उनकी इनकम के लिए एक तय सोर्स पर काम किया जाएगा। वहीं एक मजबूत दूध सप्लाई चेन बनाने की जरूरत पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि एनडीडीबी सहकारी दूध खरीद को बढ़ावा देने, सप्लाई गतिविधियों को मजबूत करने, उपभोक्ताओं के लिए क्वालिटी वाला दूध और डेयरी प्रोडक्ट तय करने के लिए डेयरी प्रोसेसिंग के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने पर जोर देगी।

बायो फर्टिलाइजर से आएगा बदलाव

डॉ. मीनेश शाह का कहना है कि एनडीडीबी राज्य के ग्रामीण आजीविका अवसरों में भी सुधार करेगी। डॉ. शाह ने एनडीडीबी की खास पहल के बारे में बात करते हुए खाद प्रबंधन मॉडल के बारे में विस्तार से बताया। बायोगैस और बायो फर्टिलाइजर की मदद से बायो साईकिल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की कोशिशों पर रोशनी डाली। उनका कहना है कि ऐसा करने से राज्य में जैविक कृषि को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने गोबर से समृद्धि पहल के बारे में भी चर्चा की, जो बायोगैस प्रतिष्ठानों के लिए कार्बन वित्तपोषण और किसानों के लिए पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ दोनों को बढ़ाने के लिए डेयरी खेती में खासतौर पर प्रथाओं को एकीकृत करने पर केंद्रित है।

जागत गांव हमार, सलाहकार मंडल

1. **प्रो. डा. केआर मौर्य, पूर्व कुलपति,** राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसासमस्तीपुर (बिहार) एवं महात्मा ज्योतिराव फूले विश्वविद्यालय, जयपुर (राजस्थान) ईमेल-kuber.ram@gmail.com, मोबा- 7985680406
2. **प्रो. डा. गैब्रियल लाल, प्रोफेसर,** आनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग सैम हिंगिन बॉटम यूनिवर्सिटी आफ एग्रीकल्चर, टेक्नालोजी एंड साइंसेज, प्रयागराज, उप्र। ईमेल- द्दुद्बद्धह्नiyal.lal @shiats.edu.in, मोबा- 7052657380
3. **डा. वीरेन्द्र कुमार,** प्रोफेसर एंड हेड, पौध रोग विज्ञान विभाग, डा. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय परिसर ढोली, मुजफ्फरपुर बिहार। ईमेल- birendraray@gmail.com मोबा- 8210231304
4. **डा. नरेश चन्द्र गुप्ता, वैज्ञानिक,** मृदा विज्ञान, कृषि महाविद्यालय बिरसा, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कॉके, रॉची झारखण्ड। ईमेल- ncguptabau@gmail.com, मोबा- 8789708210
5. **डा. देवेंद्र पाटिल, वैज्ञानिक** (शस्य विज्ञान) कृषि विज्ञान केन्द्र, सीहोर (मध्यप्रदेश) सेवनिया, इछावर, सिहोर (मप्र) ईमेल- dpatil889@gmail.com, मोबा- 8827176184
6. **डा. आशुतोष कुमार सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर,** एग्री विजनेस मैनेजमेंटकृषि अर्थशास्त्र विभाग, एकेएस,विश्वविद्यालय, सतना, मप्र ईमेल- kumar.ashu777@gmail.com, मोबा- 8840014901
7. **डा. बिनीता सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर** आनुवांशिकी एवं पौध प्रजनन विभाग एकेएस विश्वविद्यालय, सतना, मप्र ईमेल- singhvineeta123@gmail.com, मोबा- 8840028144
8. **डा. आरके शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर,** परिजीवी विज्ञान विभाग, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना, बिहार। ईमेल- drrksharmabvc@gmail.com, मोबा- 9430202793
9. **डा. दीपक कुमार, सहायक प्राध्यापक,** मृदा एवं जल संरक्षण अभियंत्रिकी विभाग, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर, उत्तराखण्ड। ईमेल- deepak.swce.cot.gbpuat@gmail.com, मोबा- 7817889836
10. **डा. भारती उपाध्याय, विषय वस्तु विशेषज्ञ** (शस्य विज्ञान) कृषि विज्ञान केन्द्र, विरौली, समस्तीपुर, बिहार। ईमेल-bharati.upadhya@rpcau.ac.in, मोबा- 8473947670
11. **रोमा वर्मा,** सब्जी विज्ञान विभाग महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं् वानिकी विश्वविद्यालय, पाटन, जिला- दुर्ग, छत्तीसगढ़। ईमेल- romaverma35371@gmail.com, मोबा- 6267535371

जबलपुर में धान घोटाला: पांच सोसायटी में 2268 मीट्रिक टन कम मिली धान

जबलपुर। धान घोटाला कर सरकार को 521 लाख रुपए की आर्थिक क्षति पहुंचाने वाले 5 धान उपार्जन सोसायटियों के 22 व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। इन पांच धान उपार्जन केंद्रों में जांच के दौरान लगभग 2268 मीट्रिक टन धान कम पाई गई। जिसके बाद प्रशासन की तरफ से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी। गौरतलब है कि जिला कलेक्टर दीपक सक्सेना के निर्देश पर धान उपार्जन सोसायटियों द्वारा खरीदी और भंडारित धान की जांच की गई थी। इस दौरान पांच उपार्जन सोसायटियों में 2268 मीट्रिक टन धान का घोटाला सामने आया।

- नर्मदा एग्रो कालाडूमर (तहसील पनागर) - 7194.79 क्विंटल धान कम, अनुमानित मूल्य 1.65 करोड़ रुपए।
- मां रेवा वेयरहाउस (मझौली) - 6068.59 क्विंटल धान कम, अनुमानित मूल्य 1.40 करोड़ रुपए।
- जय भवानी वेयरहाउस (मझौली) - 1134 क्विंटल धान कम, अनुमानित मूल्य 26 लाख रुपए।
- गुरुजी वेयरहाउस (पाटन) - 5618.60 क्विंटल धान कम, अनुमानित मूल्य 1.29 करोड़ रुपए।
- षुभी एग्रो वेयरहाउस (सिमरिया, पनागर) - 2672.25 क्विंटल धान कम, अनुमानित मूल्य 61.50 लाख रुपए।

प्रशासनिक अधिकारियों की शिकायत पर पांच धान उपार्जन सोसायटियों के खिलाफ संबंधित थानों में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने इन पांचों सोसायटियों के 22 व्यक्ति यों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है।
सूर्यकात शर्मा, एएसपी, जबलपुर

जागत गांव हमार के सुधि पाठकों...

» जागत गांव हमार कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास आधारित समाचार पत्र है, जिसके लिए आपका स्नेह और प्यार हमें शुरू से मिलता रहा है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा।

» समाचार पत्र के लिए विशेषज्ञों की राय, प्रकाशन योग्य सामग्री के साथ-साथ आपके समक्ष इसे पहुंचाने तक हमारी जिम्मेदारी बड़ी चुनौतीपूर्ण है। आपके सहयोग से ही हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे।

» ऐसे में हमारी आपसे अपेक्षा और आग्रह है कि जागत गांव हमार के वार्षिक सदस्य बनें और इसके लिए नीचे लिखे गए नंबर पर संपर्क करें।

संपर्क करें- अजय द्विवेदी-9229497393, 9425048589

"आपका सहयोग हमारी मजबूती का आधार बनेगा"

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। **संपादक:** अजय कुमार द्विवेदी, **स्थानीय संपादक:** अरविंद मिश्रा, **संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)